Proposal of new railway line from Nalgonda to Macherla via Nagarjuna Sagar

124. DR. D. VENKATESWAR RAO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Government of Andhra Pradesh had proposed to Government for laying
of new Railway line from Nalgonda to Macherla via Nagarjuna Sagar;

(b) if so, whether the State Government had stressed the need for such railway line as the area around Vijayapuri and Nagarjuna Sagar is ideal for industrial promotion;

(c) if so, whether Government have considered that proposal;

(d) if so, by when final approval is likely to be given; and

(e) if not, the reasons thereof?

1 HE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (c) Yes, Sir.

(d) and (e) It has not been found possible to consider construction of this line at this stage due to acute constraint of resources.

Stock of box wagons and box "N" wagons

125. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) to total number of box wagons and "N" wagons with the Indian Railways, separately;

(b) the codal life of such box wagons and box "N" wagons;

(c) whether there is any scheduled programme for rebuilding of the above wagons; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a)The total number of BOX and BOX "N" Wagons as on 31.3.96 were 32252 and 44630, respectively.

(b) The codal life of BOX/BOX "N" Wagons is 35 years.

(c) and (d) Rebuilding of 1000 BOX Wagons has been proposed in the Rolling Stock Programme of 1996-97. There is no programme for re-building of BOX "N" Wagons.

Alterations in Government Houses

126. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the balconies of a large number of type IV Government houses had to be reconstructed by giving support of pillars;

(b) if so, the reasons therefor and when were those houses constructed;

(c) whether the matter has been enquired into and if so, the details thereof and the action taken/proposed to be taken against the guilty officials/contractors;

(d) whether a large number of Government houses were declared dangerous and got vacated for demolition/major repairs but were instead allotted to the CPWD staff;

(e) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(f) the action taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) No, Sir. 6 balcones out of 394 Type IV quarters in R.K. Puram, Sector VIII were found distressed and were given additional support of pillar, raised from bottom. All these 6 quarters have now been repaired.

(b) The quartres were constructed in 1976. Due to corrosion of steel, the balconies had become unsafe.

(c) Reasons for the distress are being ascertained and responsibility would be fixed.

(d) and (e) Yes, Sir: 264 quarters in Delhi were takan over by the CPWD for repairs. Out of 264 quarters, 194 quarters were at various stages of repairs and some of the balance quarters were being used temporarily as stores by CPWD Field Units and a few were under occupatin of CPWD personnel on payment of licence fee.

All these 264 quartres have since been got repaired, vacated and handed over to the

Directorate of Estates except for 16 numbers, 8 of which were beyond economic repairs and are to be demolished and the balance is being used as office and stores. Further, 452 quarters in Delhi were slated for demolition and redevelopment of area. Out of these, 340 are lying vacant, 55 are under encroachment and the remaining 57 quarters are temporarily being used as Stores/Offices and residences by the CPWD staff permitted by the Field Units on their own on payment of licence fee.

(0 For irregular action by the Field Units of the CPWD, Chief Engineers have been directed by Director General (Works), C.P.W.D. to take immediate action to get the quarter vacated and to fix responsibility for these lapses.

नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उठाए गए कदम

127. **श्री इकबाल सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार ने भारत के संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर देश के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा नि:शुल्क उपलब्ध कराने तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लड़के-लड़कियों को रियायती दर पर उच्च शिक्षा दिलवाने के संबंध के किसी राष्ट्रीय-नीति का निर्माण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री भुही राम सैकिया): (क) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यथाशोधित राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में यह संकल्प किया गया है कि 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने के पूर्व ही 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करा दी जाये।

नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) सभी राज्यों में सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को शिक्षण शुल्क की अदायगी से छूट दी गई है। कई राज्यों ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के बच्चों और लड़कियों की नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, स्कूल की वर्दी और अन्य प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान किए हैं।

केन्द्रीय सरकार ने संपूर्ण देश में प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1995-96 में प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम शुरू किया है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत कंपनियों के कोयले के स्टॉक की ओवर रिपोर्टिंग किया जाना

128. **श्री दिलीप सिंह जुदेव:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कंपनियों में वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान कोयले के स्टॉक की ओवर रिपोर्टिंग करने के आरोप सिद्ध हो गये है;

(ख) प्रत्येक कंपनी के वास्तविक स्टॉक और सूचित स्टॉक के मध्य कितना अंतर पाया गया है और इस अंतर का मूल्य कितना आंका गया है;

(ग) ओवर-रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध 30 नवम्बर, 1995 तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) कोल इंडिया लिमिटेड (कोइलि॰) के अंतर्गत 3 कंपनियों में ही कोयले के स्टॉक में कमी पाई गई थी अर्थात् ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि॰, भारत कोकिंग कोल लि॰ और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि॰, जिसका 1994-95 के अंत में कोयले के स्टॉक का वार्षिक रूप में मापन किये जाने के बाद पता चला था। 1995-96 के अंत में कोयले के स्टॉक के मापन के संबंध में निरीक्षण जांच का कार्य प्रगति पर है।

(ख) 1994-95 के अंत में मापित स्टॉक तथा कोयले के पुस्तिका स्टॉक के बीच अंतराल मापन अशुद्धि की 5 प्रतिशत से अधिक स्वीकार्य सीमा से बढ़ गया था जो कि नीचे दर्शायी गई है:-

कंपनी	कमी मि॰ टन में	मूल्य करोड़ रु॰ में
ई. को. लि.	0.22	12.6
भा. को. को. लि.	2.92	132.45
सें. को. लि.	6.51	269.98